नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 02
अंक : 007
दि. 07.05.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

यूएस-ईरान पीस डील : खत्म होगा युद्ध? हो रहा है 14 बिंदुओं पर गुप्त समझौता, जिससे शांति की उम्मीद

(जीएनएस)।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध की स्थिति को खत्म करने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हलचल शुरू हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों देश एक 14-पॉइंट के समझौते (MoU) पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद फिलहाल चल रही दुश्मनी को रोकना और परमाणु मुद्दों पर लंबी बातचीत का रास्ता खोलना है।

हालांकि अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यह तनाव कम करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम है। इस समझौते के तहत 30 दिनों का एक 'नेगोशिएशन विंडो' खुलेगा, जिसमें बड़े विवादों को सुलझाया जाएगा।

यह समझौता महज एक पन्ने का है, जिसमें 14 मुख्य बातें लिखी गई हैं। इसका पहला लक्ष्य तुरंत 'सीजफायर' यानी गोलाबारी रोकना है। इसके बाद 30 दिनों का समय तय किया गया है, जिसमें दोनों देश बैठकर एक स्थाई समाधान ढूंढेंगे। अगर यह सफल रहा, तो इसे आधिकारिक तौर पर "युद्ध की समाप्ति" माना जाएगा। इस दौरान ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाएगा और बदले में अमेरिका उस पर लगी पाबंदियों में ढील देना शुरू कर देगा।

पाबंदियां हटेंगी और पैसा होगा रिलीज

समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर वापस करेगा। इसके साथ ही ईरान के व्यापार पर लगी कड़ी पाबंदियां भी हटाई जाएंगी। बदले में ईरान को यूरेनियम संवर्धन का काम रोकना होगा। इसके अलावा, दोनों देश होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता आसान बनाने और वहां सैन्य तनाव कम करने पर भी सहमत हुए हैं। इससे वैश्विक तेल बाजार को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

यूरेनियम पर 'टाइम लिमिट' का पेंच

सबसे ज्यादा बहस इस बात पर है कि ईरान कितने सालों तक परमाणु काम रोके रखेगा। अमेरिका चाहता है कि यह रोक 20 साल के लिए हो, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल की बात कह रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 से 15 साल के बीच कोई समझौता हो सकता है। इस समय सीमा के बाद ईरान को केवल 3.67% तक ही यूरेनियम संवर्धित करने की इजाजत होगी, जो परमाणु बम बनाने के लिए काफी नहीं होता।

कड़ी निगरानी और सुरक्षा शर्तें

अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों को बंद करे। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र (UN) के

इंस्पेक्टरों को कभी भी, कहीं भी जांच करने की आजादी दी जाए। एक प्रस्ताव यह भी है कि ईरान के पास मौजूद 'हाई एनरिच्ड यूरेनियम' का स्टॉक अमेरिका को सौंप दिया जाए। अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बना सके, और अगर वह नियम तोड़ता है, तो पाबंदियां दोबारा लगा दी जाएं।

ये भी पढ़ें: लड्ढ१४९ उ१२२: बीच समंदर फंसा अमेरिकी जहाज, न

को लेकर दो फाड़ हैं, जिससे बात बिगड़ सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी ईरान की विश्वसनीयता पर शक जताया है, हालांकि उन्होंने माना कि तकनीकी बारीकियों को सुलझाने में समय लगेगा। अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। अगर बात बनी, तो अगली बड़ी बैठक इस्लामाबाद या जिनेवा में हो सकती है।

ट्रंप ने क्या कहा?

वहीं इस समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि, 'अगर ईरान उन बातों को मान लेता है जिन पर सहमति बनी है-हालांकि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है-तो हमारा सैन्य अभियान 'एपिक फ्यूरी' खत्म हो जाएगा। इसके बाद, जो सख्त नाकाबंदी हमने लगा रखी है, उसे हटा लिया जाएगा और हॉर्मुज समुद्री रास्ता ईरान समेत सबके लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अगर वे बात नहीं मानते, तो बमबारी फिर से शुरू होगी, और इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और तेज होगा।

पीएम मोदी की लोकप्रियता असाधारण, उनके आसपास विश्व का कोई नेता नहीं एरिक सोल्हेम

ट्रंप सहित विश्व भर के नेताओं से तुलना करते हुए कहा 'मोदी ने अपनी मेहनत और देश के विकास के विजन के दम पर जितनी लोकप्रियता हासिल की है, उसके आसपास भी कोई भी नहीं पहुंचता'।

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, नॉर्वे के पूर्व जलवायु और पर्यावरण मंत्री एरिक सोल्हेम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व भर के नेताओं से तुलना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मेहनत और देश के विकास के विजन के दम पर जितनी लोकप्रियता हासिल की है, उसके आसपास भी कोई भी नहीं पहुंचता।

सोल्हेम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए

कहा कि लोकतंत्र में किसी नेता के लिए लंबे समय तक इतनी मजबूत जनसमर्थन बनाए रखना बहुत ही दुर्लभ होता है।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी भारत में बेहद लोकप्रिय हैं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई नेता इतने लंबे समय तक इतना बड़ा समर्थन जुटा पाए, जैसा पीएम मोदी ने किया है।'

सोल्हेम ने आगे कहा, 'शायद 1950 के दशक में जब यूरोप में लगातार तेज विकास हो रहा था, तब वहां के नेता ऐसा सपना देख सकते थे, लेकिन आज के समय में यह बहुत ही खास और अलग बात है।'

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स कंपनी 'मॉर्निंग कंसल्ट' के एक सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। 2 से 8 मार्च के बीच किए गए इस सर्वे के मुताबिक, एनालिटिक्स फर्म ने कहा कि पीएम मोदी 68 प्रतिशत की मजबूत अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के बाकी नेताओं से काफी आगे हैं।

सोल्हेम ने कहा, 'फिलहाल मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी नेता अपने देश में प्रधानमंत्री मोदी जितना लोकप्रिय है।'

बंगाल में चुनाव जीतते ही बांग्लादेश ने पीएम मोदी से की मांग, 1983 से अटके तीस्ता विवाद पर वार्ता का अनुरोध किया

प. बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा की जीत को सिर्फ राज्य में ही नहीं, बल्कि सीमा पार बांग्लादेश में भी समर्थन मिला है। बांग्लादेश की सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने ढाका से इखढ को बधाई संदेश भेजा और साथ ही लंबे समय से अटके तीस्ता जल-बंटवारा समझौते पर फिर से विचार करने की मांग भी रखी। ममता बनर्जी को माना जाता था बड़ी बाधा ढाका लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारत-बांग्लादेश के बीच तीस्ता विवाद सुलझाने में बड़ी रुकावट मानता रहा है।

लखनऊ में 'फ्रूट होराइजन 2026' कार्यक्रम में शामिल होंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से शुरू हो रहे फ्रूट होराइजन 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य देश में फल उत्पादन, गुणवत्ता संवर्धन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों को एक साझा मंच पर लाकर फल क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान करना है।

श्री चौहान निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद

करेंगे। वे आज प्रगतिशील निर्यातकों से भी मिलेंगे और निर्यातकों, निदेशकों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करेंगे। इन चचाओं से देश के फल व्यापार को मजबूती मिलने और किसानों के लिए बेहतर अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

मुख्य कार्यक्रम कल आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय संस्थान में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वे किसानों, नर्सरी हितधारकों और प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद मुख्य सत्र होगा। इसमें राज्य सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और दिनेश प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन से बागवानी और फल निर्यात के क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और बाजार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

नेवी के लिए डीआरडीओ ने बनाई घातक मिसाइल

(जीएनएस)।

भारत ने हाल ही में ओडिशा तट से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल छफ-अरँट की सफल टेस्टिंग की है। यह मिसाइल DRDO द्वारा बनाई गई है, जिसकी रेंज 1,500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट करने की है। ये मिसाइल भारत के लिए क्यों जरूरी थी, कैसे काम करती है और क्या है इसकी खासियत सब जानेंगे।

क्या खास है इस मिसाइल में?

LR-AShM एक टू-स्टेप वाली, सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जो मैक 5 से लेकर मैक 10 तक की स्पीड बहुत कम समय में हासिल कर सकती है। यह कम ऊंचाई पर उड़ते हुए, सेमी-बैलिस्टिक ट्रैक पर स्किप करती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। इसमें इंडियन मेड सेंसर लगे हैं जो लास्ट स्टेप में चलते हुए टारगेट, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, को भी सटीक ढंग से निशाना बना सकते हैं। इसकी टर्मिनल गाइडेंस और हाई-स्पीड मैन्युवरिंग (हवा में बार-बार घूमना या चक्कर खाना) इसे बेहद घातक बनाती है।

हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ सामरिक तनाव ने भारत को अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए मजबूर किया। खासकर चीन की एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित रणनीति को देखते हुए, भारत को ऐसी मिसाइल

की जरूरत थी जो लंबी दूरी से दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सके। छफ-अरँट इसी जरूरत का जवाब है, जो भारत की A2/AD (Anti-Access/Area Denial) क्षमता को मजबूत करती है, यानी दुश्मन को भारत के समुद्री क्षेत्र के करीब आने से रोकना। इस मिसाइल का उपयोग युद्ध के दौरान दुश्मन के बड़े युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसैनिक ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। यह खास तौर पर उन परिस्थितियों में अहम होगी जब दुश्मन समुद्र के रास्ते भारत के करीब आने की कोशिश करेगा। इसकी लंबी रेंज और हाइपरसोनिक स्पीड भारत को स्टैंड-ऑफ अटैक की क्षमता देती है, यानी बिना पास गए ही दुश्मन को खत्म करना। LR-AShM प्रोजेक्ट की सटीक लागत सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की गई है। हालांकि, डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि हाइपरसोनिक तकनीक के विकास में हजारों करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें एडवांस्ड मटेरियल, प्रोपल्शन और गाइडेंस सिस्टम शामिल होते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिससे लंबे समय में लागत कम होती है। इस मिसाइल के आने से चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चीन, जो हिंद महासागर में अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है, अब भारत की इस कैपेसिटी के कारण अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर होगा। साथ ही, वहीं पाकिस्तान के लिए भी यह एक मजबूत संदेश है कि भारत अब समुद्री युद्ध में भी हाई-टेक और तेज प्रतिक्रिया देने में सक्षम है।

भीषण गर्मी से बड़ी राहत, सीएम गुप्ता ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को दिखाई हरी झंडी

राजधानी दिल्ली में सूरज के तीखे तेवर और बढ़ते तापमान के बीच केजरीवाल सरकार ने आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री

श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह कदम विशेष रूप से सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों, यात्रियों और खुले में रहने वाले लोगों को लू के घातक प्रभाव से बचाने के लिए उठाया गया है।

दिल्ली सरकार का यह प्रयास न केवल तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेगा, बल्कि भीषण गर्मी में डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक जैसी आपात स्थितियों को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा।

बेरहमी से की गई सुनियोजित हत्या', पीए रथ की हत्या पर बोले सुवेंदु, टीएमसी ने ट्वीट कर की भर्तसना

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल एक बार फिर से नफरत और हिंसा की आग में जल रहा है, बुधवार रात उत्तर 24 परगना जिले का मध्यग्राम इलाका तब दहल उठा जब BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। सुवेंदु के राईट हैंड कहे जाने वाले चंद्रनाथ इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें तुरंत डायवर्सिटी नर्सिंग होम ले जाया गया, पर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकताओं पर लगा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

चंद्रनाथ को गोली लगने की बात सुनते ही सुवेंदु भी अस्पताल पहुंचे थे, उन्होनें इसे 'बेरहमी से की गई सुनियोजित हत्या' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला योजनाबद्ध था और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी को दे दी गई है, ये सबकुछ 15 साल के महाजंगलराज का नतीजा है,

भाजपा अब राज्य में गुंडागर्दी खत्म करने का काम करेगी।'

तो वहीं टीएमसी ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। उसने एक्स पर लिखा कि 'हम आज रात मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही, हम पिछले तीन दिनों में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं में तीन अन्य TMC कार्यकताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं।'

'आरोप है कि ये हिंसक वारदातें BJP-समर्थित उपद्रवियों द्वारा की गई हैं, जबकि इस दौरान 'आचार संहिता' लागू थी। हम इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें अदालत की निगरानी में CBI जांच भी शामिल है, ताकि दोषियों की पहचान हो सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं के लिए कोई जगह नहीं है, और दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।'

नेपाल जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब ऑनलाइन बनेगा गाड़ी का भंसार, बालेन सरकार का फैसला

नेपाल सरकार ने भारतीय वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत दी है। अब भारत से नेपाल जाने वाली कारों और बाइकों को बॉर्डर पर घंटों लाइन में

लगकर कागजी 'भंसार' (परमिट) नहीं बनवाना पड़ेगा। पीएम बालेन सरकार ने ऑनलाइन भंसार सेवा शुरू की है, जिससे आप घर बैठे ही डिजिटल तरीके से रजिस्ट्रेशन और टैक्स भुगतान कर सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सीमा चौकियों पर लगने वाली भीड़ को कम करना और यात्रा को सुगम बनाना है।.

प्रयागराज: सीएम योगी ने किया रक्षा प्रदर्शनी का किया अवलोकन, बोले- हमारी उदारता को न समझें कमजोरी

प्रदर्शनी में आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप विकसित तकनीकों और उपकरणों ने भारत की शक्ति दिखाई गई.

(जीएनएस)।

नॉर्थ टेक सिम्पोजियम-2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एग्जीबिशन का अवलोकन करते हुए देश की उभरती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं की सराहना की. तीन दिवसीय इस आयोजन में आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप विकसित अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का व्यापक प्रदर्शन किया गया, जिसमें सेना, उद्योग और स्टार्टअप्स की सहभागिता स्पष्ट रूप से दिखाई दी.

प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री ने बुलेटप्रूफ जैकेट, टैक्टिकल गियर, अत्याधुनिक हेलमेट और मल्टी-टेरेन ऑपरेशंस के लिए विकसित सैन्य

उपकरणों का बारीकी से निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विशेषज्ञों से तकनीकी विशेषताओं की जानकारी ली और उत्पादों की उपयोगिता पर चर्चा की. विशेष रूप से 'हेड-टू-बूट' सुरक्षा प्रणाली, अत्यधिक विषम तापमान में पहने जाने वाले कपड़े और मॉड्यूलर प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे इनोवेशन आकर्षण का केंद्र रहे.

सिम्पोजियम में प्रदर्शित तकनीकों में ड्रोन, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, कम्युनिकेशन उपकरण और भविष्य के युद्धक्षेत्र के लिए विकसित एआई आधारित समाधान भी शामिल रहे. यह आयोजन इस बात का संकेत है कि भारत अब पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर मल्टी-डोमेन वॉरफेयर यानी साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में भी अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है. प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और रक्षा कंपनियों की भागीदारी ने 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती दी है.

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर सहारनपुर में रूट डायवर्ट, इन वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल

(जीएनएस)।

सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को देवबंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में आने वाले कार्यकर्ता, पदाधिकारियों व आमजन मानस की भीड़ को देखते हुए सहारनपुर-मुजफ्फरनगर मार्ग पर यातायात परिवर्तित किया है।

एसपी ट्रैफिक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वह जाम व अन्य दिक्कतों से बचने के लिए जारी किए गए रूटों पर ही यात्रा करेंगे। पुलिस ने एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस व आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस रूट पर चलने की छूट दी है।

इन रूटों का करें इस्तेमाल - सहारनपुर से देवबंद होकर मुजफ्फरनगर जाने वाले भारी वाहन कस्बा गागलहेड़ी, बडकला फ्लाईओवर, भगवानपुर मार्ग से होकर भेजे जाएंगे। वहीं हल्के वाहन सहारनपुर से देवबंद, बरला तिराहा, देवबंद-बरला मार्ग होते हुए छपार से मुजफ्फरनगर की ओर जाएंगे.

- मुजफ्फरनगर से देवबंद होते हुए सहारनपुर आने वाले हल्के वाहनों को रोहाना टोल, बर्फी, ग्राम चंदली, पंचकुड़ी मार्ग, पावटी कलां, चौहड़ा और काशीरामपुर होते हुए जामिया तिब्बिया कालेज के रास्ते सहारनपुर भेजा जाएगा।

बिजनौर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौ मई को अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम आलमपुर गांवड़ी में कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

उधर जनसभा में भीड़ जुटाने में जहां भाजपा नेता जुटे हुए हैं। जनपद के प्रशासनिक अफसर भी ग्राम आलमपुर गांवड़ में 10 से 15 हजार लोगों की व्यवस्था करने में जुटे है। दो दिन पहले डीएम जसजीत कौर, एसपी अभिषेक झा और सीडीओ रणविजय सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के बाद जनसभा स्थल का निरीक्षण किया था।

इस दौरान डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियो से विभिन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तलब की थी। सीडीओ रणविजय सिंह का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं मिला है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी की जा रही है।

लखनऊः बेटे की शादी के दिन पिता की मौत, चिता को आग देने के बाद दूल्हा बनकर गया बेटा; खुशियों की जगह मातम

(जीएनएस)।

लखनऊ। लखनऊ के निगोहां क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक पिता की मौत उसी दिन हुई जिस दिन उसके बेटे की शादी थी।

पूरा घर मंगल गीतों से गूंज रहा था। विवाह की रस्में धूमधाम से चल रही थीं। पूरे गांव में बरात निकलने की तैयारियां हो रही थीं कि तभी अचानक दूल्हे के पिता की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले गए पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। शादी वाले घर में शहनाई की जगह क्रंदन गूंज उठा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पिता का अंतिम संस्कार कर दूल्हा देर शाम कुछ लोगों के साथ बरात लेकर दुखी मन से रायबरेली रवाना हुआ और वहां विवाह की रस्मअदायगी कर बुधवार को वापस आया। गांव में बरात आने की खुशियों की जगह मातमी सन्नाटा पसरा रहा।

मामला राजधानी के निगोहां गांव का है जहां 60 वर्षीय किसान भाईलाल कश्यप के सबसे छोटे बेटे रिंकू की मंगलवार को शादी थी। शाम को बरात रायबरेली के शिवगढ़ स्थित गांव बंकागढ़ जानी थी। बरात के लिए घर में रिश्तेदार जमा थे और गांव भर में तैयारियां चल रही थीं। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सोमवार शाम हल्दी-मेहंदी की रस्म के दौरान भाईलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। परिजनों ने निगोहां कस्बा स्थित एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। भाईलाल की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर दूसरी ओर कन्या पक्ष तक जब खबर पहुंची तो वहां भी मातम छा गया।

भाईलाल के परिजन सकते में थे क्योंकि अंतिम संस्कार भी होना था और मंगलवार को ही बरात भी जानी थी। नाते-रिश्तेदारों की रजामंदी से तय हुआ कि भाईलाल के अंतिम संस्कार के बाद सादगी के साथ बरात रवाना होगी। मंगलवार शाम लगभग चार बजे गांव में ही भाईलाल का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद भारी मन से रात लगभग आठ बजे सीमित बरातियों के साथ बरात रायबरेली के शिवगढ़ में स्थित बंकागढ़ निवासी रामनंद के यहां रवाना हुई। पहले से तय कार्यक्रम के चलते सादगी के साथ किसी तरह से विवाह की रस्में पूरी कराई गईं। बुधवार को रिंकू कश्यप अपनी नई नवेली दुल्हन रोहिनी को लेकर घर पहुंचे। इस दौरान घर-परिवार और गांव में उल्लास की जगह गम और सन्नाटा था। इस हृदयविदारक घटना की पूरे क्षेत्र में चर्चा रही। गांव वाले यही कह रहे थे कि भगवान ऐसा दिन किसी को भी न दिखाए।

लखनऊ में आईपलएल मैचों के दौरान सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले कैमरे बंद, गोमती नगर विस्तार में केस दर्ज

(जीएनएस)।

लखनऊ। इकाना स्टेडियम में गुरुवार को आईपीएल 2026 में गत विजेता रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले मुकाबले से पहले ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। शहीद पथ पर लगे 40 कैमरे सीसीटीवी के उपकरण चोरी होने के कारण बेकार हैं। गोमती नगर विस्तार थाना में इस प्रकरण को लेकर केस दर्ज किया गया है।

लखनऊ में गोमती नगर विस्तार में सेफ सिटी परियोजना के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों के उपकरण (स्विच, बैटरी, यूपीएस) चोरी हो गए हैं। जिसके कारण शहीद पथ पर करीब 40 कैमरे बंद हो गए हैं। इस चोरी से ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

इन 40 कैमरों का उपयोग आईपीएल के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी किया जाता था। गोमती नगर विस्तार और शहीद पथ क्षेत्र में स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाए गए कैमरों के स्विच, बैटरी और यूपीएस को चोर उठा ले गए। इसके कारण 40 कैमरे बंद हैं। इस चोरी के बाद महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर असर पड़ेगा।

कैमरों का इस्तेमाल यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की निगरानी और आईपीएल मैचों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट में किया जाता था। महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए भी कैमरे अहम भूमिका निभा रहे थे। उपकरण गायब होने से फिलहाल कैमरे बंद पड़े हैं। पुलिस ने मामले इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरी करने वालों की पहचान की जा सके।

लखनऊ में जमीन न मिलने से अनूपगंज आरओबी की फंस गई सर्विस लेन, दो वर्ष से लटका पड़ा काम

आरओबी को रेलवे क्रासिंग संख्या 188 स्पेशल पर बनाया जा रहा

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पंद्रह लाख आबादी को राहत देने वाले रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के कार्य की रफ्तार भले संतोषजनक हो, लेकिन सर्विस रोड न बन पाने के कारण यहां से गुजरने वाली एक बड़ी आबादी को परेशानी हो रही है।

यहां पर जहां पर सर्विस रोड का निर्माण होना था, वहां काश्तकारों ने अभी तक जमीन नहीं दी है। गोसाईगंज में बलियाखेड़ा के 103 काश्तकार और शिवलर के छह काश्तकार है। कुल 109 काश्तकारों में सिर्फ 75 काश्तकार ने जमीन देने पर सहमति दी है। बाकी काश्तकारों की जमीनों की रजिस्ट्री होनी बाकी है। इससे यहां सर्विस लेन नहीं बन पा रही है। एक बड़ी आबादी को पिछले डेढ़ वर्ष से परेशानी उठानी पड़ रही है।

यही नहीं शुरू में कार्यदायी संस्था ने आरओबी से जुड़े काम को भी धीमी गति से किया, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के एमडी के कार्यदायी संस्था को नोटिस देने के बाद काम की रफ्तार में कुछ सुधार हुआ। अधिकारियों के मुताबिक मार्च 2024

में शुरू हुए काम के हिसाब से रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का साठ प्रतिशत काम हो गया है। 718.678 मीटर लंबे आरओबी के निर्माण 14,044.78 लाख रुपये खर्च आ रहा है। निगम के अभियंताओं को आरओबी का काम मार्च 2028 तक पूरा करना है।

चार लेन के इस आरओबी को रेलवे क्रासिंग संख्या 188 स्पेशल पर बनाया जा रहा है। इस आरओबी के निर्माण से सुलतानपुर रोड से रायबरेली रोड व कानपुर रोड का सफर आसान हो जाएगा। इसके अलावा गोसाईगंज से सीधे मोहनलालगंज होते हुए प्रयागराज की कनेक्टिविटी मिल जाएगी एवं प्रयागराज आने वाले यातायात सुलतानपुर रोड पर जाने के लिए सीधे जुड़ा जाएंगा। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए दिल्ली, बरेली, सीतापुर, हरदोई आने जाने वाले भारी एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात सुगम हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि 109 काश्तकारों में 75 काश्तकारों ने जमीन देने पर सहमति दे दी है। बचे हुए काश्तकारों की प्रकिया चल रही है। बता दें कि यहां तीन से चार परिसर भी रेलवे क्रासिंग से पहले आ रहे हैं, उन्हें तोड़ा जाएगा। इसमें एक परिसर शांति मिश्रा का है जो अपने सेतु निगम की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने चार मंजिला इमारत को निगम की गाइडलाइन के हिसाब से पीछे करवा रही हैं।

वहीं सेतु निगम के मुताबिक काश्तकारों को 2652.82 लाख रुपये मुआवजे के रूप में वितरित किया जाएगा। इसमें सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत और जिनके परिसर आ रहे हैं, उसकी एक निर्धारित कीमत भी प्रशासन देगा। अगर वह अपना परिसर पीछे भी अपनी जमीन पर कर लेते हैं, तब भी यह धनराशि उन्हें दी जाएगी।

अब थमेगी प्रदेश में बारिश, फिर लौटेगी सताने वाली गर्मी, दस डिग्री चढ़ेगा पारा; जानें वैज्ञानिकों की कारण

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम साफ होने के साथ गर्मी फिर बढ़ने लगी है। बारिश कम होने से तापमान में लगातार वृद्धि होगी और उमस भी बढ़ेगी। अगले कुछ दिनों में तापमान 8 से 10 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश में गर्मी दोबारा वापसी के लिए तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में विक्षोभ कमजोर पड़ा है और बुधवार को सिर्फ सिद्धार्थनगर आदि तराई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बृहस्पतिवार से प्रदेश में बारिश का

दायरा सिमट जाएगा और तापमान में क्रमशः बढ़ोतरी दर्ज होगी। साथ ही हवा में नमी की मौजूदगी की वजह से उमस भरी गर्मी में इजाफा होगा। बृहस्पतिवार के लिए कहीं भी आंधी या बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।

बुधवार को 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सर्वाधिक गर्म रहा। वहीं उरई में 37.2 डिग्री और झांसी में 36.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। 16 डिग्री के साथ नजीबाबादी में सबसे ठंडी रात रही। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को तराई और दक्षिणी जिलों में हल्की बूंदाबांदी संभावित है। शुक्रवार से बारिश थमने के बाद अगले सात दिनों में तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की बढ़त आएगी।

65 रुपये की किताब ₹700 में बेची, जांच में फंसे लखनऊ के दो नामी स्कूल, नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहे अब

(जीएनएस)।

लखनऊ। जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा जारी नोटिस के बावजूद के निजी विद्यालयों की मनमानी नहीं रुक रही है। समिति के नोटिस तक का जवाब नहीं दे रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शीलवती आइडल पब्लिक स्कूल और एलन हाउस पब्लिक स्कूल ने बुधवार को अपना जवाब दे दिया है।

विद्यालय प्रशासन अभिभावकों को एक निर्धारित दुकान से ही किताबें खरीदने का दबाव बना रहा था, जांच

में आरोप भी सही पाया गया। एनसीइआरटी की 65 रुपये कीमत वाली किताबें निजी प्रकाशकों के माध्यम से 700 रुपये में दी जा रही थी। विद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा था।

विद्यालय के पक्ष और समिति द्वारा गठित जांच कमेटी के बीच विरोधाभास है। रिपोर्ट और विद्यालयों के पक्ष की जांच अगले दो दिनों में पूरी हो जाएगी। इसी सप्ताह कार्रवाई भी होगी। 25 विद्यालयों के विरुद्ध अभिभावकों ने शिकायत की थी। तीन विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की कई। अन्य का अभिभावकों की मौजूदगी में निस्तारण कर दिया गया।

लखनऊ या नोएडा, निवेश के लिए कौन सा शहर है 'हॉट' डेस्टिनेशन?

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट बाजार इस समय अपने सबसे बेहतर युग से गुजर रहा है, जहां साल 2025 में कुल निवेश का आंकड़ा 68,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया, वहीं 2026 के 4 महीने में ही 25 हजार से ज्यादा निवेश किया जा चुका है. इस विकास यात्रा के केंद्र हैं यूपी के दो बड़े शहर नोएडा और लखनऊ हैं.

लंबे समय तक नोएडा सबसे ज्यादा डिमांड में रहा है. लेकिन यूपी रेरा के ताजा आंकड़े एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं. साल 2025 में जहां नोएडा में 69 नए प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए, वहीं लखनऊ 67 प्रोजेक्ट्स के साथ उसे कड़ी टक्कर दे रहा है. 2026 की शुरूआत में भी यह रुझान बरकरार है, जो यह दशार्ता है कि अब निवेशक और डेवलपर्स दोनों ही राजधानी लखनऊ को निवेश के एक 'पावर सेंटर' के रूप में देख रहे हैं.

वहीं नोएडा का सबसे बड़ा आकर्षण इसका विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और जेवर इंटरनेशनल

एयरपोर्ट जैसी मेगा परियोजनाएं हैं. दिल्ली-एनसीआर का हिस्सा होने के कारण यहां अंतरराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियों और डेटा सेंटर्स की भरमार है. जो इसे रेंटल इनकम के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनाता है.

हालांकि, नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतों में अब ठहराव देखा जा सकता है, जिससे यहां भविष्य में कीमतों में बहुत अधिक उछाल की गुंजाइश सीमित है. यहां का जीवन काफी तेज है, लेकिन प्रदूषण और कंक्रीट के बढ़ते जंगल जीवन की गुणवत्ता के सामने बड़ी चुनौती पेश करते हैं.

इसके विपरीत, लखनऊ इस समय 'कैपिटल एप्रिसिएशन' यानी संपत्ति के दामों में बढ़ोतरी के मामले में नोएडा से आगे निकलता दिख रहा है. अमर शहीद पथ, सुल्तानपुर रोड और आउटर रिंग रोड जैसे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विस्तार ने निवेशकों को आकर्षित किया है. लखनऊ में जमीन और फ्लैट की कीमतें नोएडा के मुकाबले अभी भी कम हैं, जिससे मध्यम वर्गीय निवेशकों के लिए यहां मुनाफे की संभावना अधिक है. साथ ही, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी होने और बेहतर वायु गुणवत्ता के कारण लोग यहां रहने को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. यूपी रेरा की हालिया रिपोर्ट बताती है कि लखनऊ अब सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि व्यावसायिक लाभ के लिए भी एक बड़ा ग्रोथ हब बन चुका है.

यह भी पढ़ें: क्या काले धन को खपाने का जरिया है रियल एस्टेट, रेरा पर क्यों नहीं है लोगों को भरोसा!

2026 में निवेश का फैसला आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है, अगर आप तुरंत और सुरक्षित रेंटल इनकम चाहते हैं और आपका बजट अधिक है, तो नोएडा आपके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि में अपनी संपत्ति की कीमत को दोगुना या तिगुना होते देखना चाहते हैं और एक किफायती बजट में निवेश की तलाश में हैं, तो लखनऊ निश्चित रूप से एक 'गोल्ड माइन' साबित होगा. यूपी रेरा द्वारा फ्लैट ट्रांसफर फीस में की गई हालिया कटौती और नियमों में पारदर्शिता ने दोनों ही शहरों में घर खरीदारों के विश्वास को और मजबूत किया है.

स्मार्ट मीटर प्रीपेड होगा या पोस्टपेड? बिलिंग पर संशय बरकरार, लखनऊ के दिशा-निर्देशों सम्बंधी आदेश का इंतजार

(जीएनएस)।

कानपुर। सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर रोक भले ही लग दी हो, लेकिन केस्को में अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं है। केस्को के अधिकारी दिशा-निदेर्शों (एसओपी) के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे कुछ अधिकारी बता रहे हैं कि मई महीने का जो एक जून बिल आएगा, वह पोस्टपेड आधारित होगा। नए कनेक्शन में उपभोक्ता को पोस्टपेड स्मार्ट मीटर मिलेगा या फिर प्रीपेड, इस बारे में भी अधिशासी अभियंता-मीटर कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं।

महानगर में केस्को के 7.70 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें 1.41 लाख कनेक्शनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से

बिलिंग हो रही है। पिछले दिनों काफी विरोध को देखते हुए सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक लगा दी। इसके बाद उपभोक्ता यह जानने के लिए परेशान हैं कि अब उन्हें बिल का भुगतान प्रीपेड या पोस्टपेड बिलिंग के आधार पर करना होगा।

इस बारे में अधिशासी अभियंता-स्मार्ट मीटर सुनील आर्यन का कहना है कि उनका काम उपभोक्ता को कनेक्शन मिलने के बाद मीटर इंस्टालेशन का है। वह आनलाइन मीटर नंबर दर्ज कर मुख्यालय शक्ति भवन को फारवर्ड करते हैं। फिर वहीं से स्मार्ट मीटर की बिलिंग प्रीपेड रहेगी या पोस्टपेड, निर्धारित होता है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को बिल पोस्टपेड या प्रीपेड के हिसाब में अदा करने होंगे, यह सब शक्ति भवन लखनऊ से तय होगा। दूसरी तरफ, न्यू सर्विस कनेक्शन सेल के अधिशासी अभियंता दीपक शुक्ला का कहना है कि कनेक्शन देकर मीटर लगाना उनका काम है, लेकिन मीटर पोस्टपेड होगा या प्रीपेड, यह तय करना स्मार्ट मीटर के अधिशासी अभियंता का है।

नए कनेक्शन के साथ स्मार्ट मीटर लगाने में भी दरें हर बार बदल रही हैं। उपभोक्ताओं ने बताया कि वर्ष 2018 से 2022 तक शुरूआती दौर में एक किलोवाट का कनेक्शन स्मार्ट मीटर समेत 1,799 रुपये का था और दो किलोवाट के कनेक्शन पर 2,099 रुपय लगते थे। यह दरें बढ़कर वर्तमान में एक किलोवाट के कनेक्शन पर 5,300 और दो किलोवाट पर 5,600 रुपये से भी अधिक खर्च आ रहा है।

बढ़ी दरों में दो किलोवाट के कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर की लागत 2800, लाइन चार्ज 1400 रुपये के साथ ही 600 रिचार्ज दिया जा रहा है। जबकि, एक किलोवाट में रिचार्ज की कीमत आधी अर्थात 300 रुपये लिए जा रहे हैं। कमर्शियल के दो किलोवाट के कनेक्शन पर 7,200 रुपये खर्च आ रहा है। इसमें 2800 रुपये का स्मार्ट मीटर के साथ ही लाइन चार्ज और 2000 रुपये रिचार्ज के लिए जा रहे हैं। लाइन चार्ज स्थिति के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी इस संबंध में एसओपी जारी नहीं हुई है। स्मार्ट मीटर से बिलिंग की जो भी प्रक्रिया निश्चित की जएगी, उसका अनुपालन किया जाएगा। रही बात नए कनेक्शन के चार्ज की तो यूपी-आरसी की तरफ स्वीकृत दरों के आधार पर ही प्राक्लन आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराए जाते हैं।

क्या टूटेगी पुरानी दूरियां? भाजपा गठबंधन पर अकाली दल का बड़ा संकेत

(जीएनएस)।

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गमार्ता जा रहा है। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल (पुनर-सुरजीत) की नेता बीबी जागीर कौर के एक बयान ने राज्य की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है।

उन्होंने साफ कहा है कि यदि पंथिक मुद्दों का सम्मानजनक समाधान होता है, तो उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है।

बीबी जागीर कौर ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता सत्ता नहीं, बल्कि सिख समुदाय से जुड़े पंथिक मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाया जाता है और समुदाय की भावनाओं का सम्मान होता है, तभी किसी भी तरह के राजनीतिक गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। उनका यह बयान इस ओर इशारा करता है कि आने वाले चुनावों में मुद्दा-आधारित गठबंधन देखने को मिल सकता है।

बीबी जागीर कौर ने स्पष्ट किया कि भाजपा के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक समझौता केवल पंजाब और सिखों के हितों पर ही आधारित होगा। उन्होंने कहा- "हम भाजपा के साथ गठबंधन के प्रति पूरी तरह बंद नहीं हैं, लेकिन हमारी पहली शर्त पंथिक मुद्दों का समाधान है। इसमें बंदी सिखों की रिहाई, धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप का अंत और एसजीपीसी के चुनावों का समय पर आयोजन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।"

गौरतलब है कि भाजपा और शिरोमणी अकाली दल का गठबंधन 1996 से चला आ रहा था, जो 2021 में किसान आंदोलनों के दौरान टूट गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव दोनों ने अलग-अलग लड़े थे, जहां अकाली दल को केवल 3 और भाजपा को 2 सीटें मिली थीं। इसके बाद से दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात अब एक बार फिर संभावित नजदीकियों की ओर इशारा कर रहे हैं। अब बीबी जागीर कौर के इस रुख से संकेत मिल रहे हैं कि पंजाब में एक बार फिर 'पुराने साथियों' का मेल हो सकता है, लेकिन इस बार चेहरे और शर्तें बदली हुई होंगी।

पंजाब की राजनीति में फिलहाल आम आदमी पार्टी (अअद), कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा जैसे कई खिलाड़ी सक्रिय हैं। ऐसे में किसी एक पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल करना आसान नहीं माना जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इसी वजह से छोटे दलों और क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका इस बार निर्णायक हो सकती है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

ईरानी स्कूल में निर्दोष नागरिकों पर हमले को लेकर पेंटागन की चुप्पी की आलोचना

पूर्व शीर्ष सैन्य वकील समेत अमेरिका के पांच पूर्व अधिकारियों ने इस साल की शुरूआत में ईरान के एक स्वूल पर हुए घातक हमले में संभावित अमेरिकी भूमिका को स्वीकार न करने पर पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय) की आलोचना की है। इनमें से वुछ ने कहा कि इतने लंबे समय बाद भी हमले की बुनियादी जानकारी तक जारी न करना बेहद असामान्य है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल युद्ध की शुरूआती कार्रवाई के दौरान मिनाब में एक प्राइमरी स्वूल पर मिसाइल गिरी। जिसमें करीब 110 बच्चे समेत 168 लोगों की मौत हुई। इसके बाद बीते दो महीनों में पेंटागन ने सिर्प इतना कहा है कि इस घटना की जांच जारी है। मार्च की शुरूआत में अमेरिकी मीडिया ने खबर दी थी कि अमेरिकी सैन्य जांचकताओं का मानना है कि शायद अमेरिकी बल अनजाने में स्वूल पर हमले के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वे अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे थे। बीबीसी ने इस हमले की पारदर्शिता की कमी के आरोपों पर कई सवाल पूछे, जिस पर पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा, इस घटना की जांच जारी है। लेफ्टिनेंट कर्नल रेचल ई वेनलैंडिंगम कहती हैं कि अमेरिका की मौजूदा स्थिति सामान्य प्रतिव्रिया से साफ तौर पर अलग है। वेनलैंडिंगम अमेरिकी वायुसेना में जज एडवोकेट जनरल रह चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने कम से कम युद्ध कानून के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता दिखाई थी। मौजूदा प्रशासन के बयानों में जबावदेही की प्रतिबद्धता गायब है। सबसे अहम यह सुनिश्चित करना भी कि ऐसा दोबारा न हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 मार्च को कहा था कि उनके विचार में मिनाब हमले के लिए ईरान जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने कोई सुबूत नहीं दिया। वुछ दिन बाद जब उनसे मिनाब स्वूल के पास सैन्य अड्डे पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल गिरने का वीडियो दिखाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहाः मैंने यह नहीं देखा। साथ ही ट्रंप ने बिना किसी सुबूत दावा किया कि ईरान के पास भी टॉमहॉक मिसाइलें थीं। 11 मार्च को जब उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया जिसमें कहा गया था कि शुरूआती सैन्य जांच में पाया गया कि अमेरिका ने स्वूल पर हमला किया था तो ट्रंप ने कहा मुझे इसके बारे में नहीं पता। अमेरिका के रक्षामंत्री पीट हेगसेथ से 4 मार्च को बीबीसी ने इस हमले पर सवाल किया था तो उन्होंने कहा, मैं सिर्प इतना कह सकता हूं कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। यही नहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस हमले पर कई सवालों के जवाब देने से इंकार कर दिया। पिछले महीने बीबीसी ने स्वतंत्र रूप से हमले की वीडियो की पुष्टि की थी जिसमें स्वूल के पास ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के अड्डे पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल गिरती दिख रही थी। पेंटागन के एक वरिष्ठ पूर्व सलाहकार वेस ब्रायंट ने बीबीसी से कहा कि शुरूआती सैन्य जांच आमतौर पर दो बातें तय करने के लिए होती है। पहली, क्या नागरिक क्षति वास्तव में हुई? दूसरी क्या उस समय अमेरिका उस इलाके में सव्रिय था या नहीं? जब दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तभी औपचारिक जांच शुरू की जाती है। प्रव्रिया के लिहाज से यह और भी साफ संकेत देता है कि वे पहले से जानते हैं कि वह अमेरिका की वजह से हुआ नहीं तो वे जांच नहीं कर रहे होते। वे बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहते या इस पर बोलना नहीं चाहते। पिछले साल अमेरिका के रक्षा विभाग ने नौकरियों की कटौती की थी, उसमें ब्रायंट भी शामिल थे।

प. बंगाल में एक अहम जीत के बाद भी वहां कि बजाये पहले पटना क्यों जा रहे हैं पीएम, है बड़ी वजह

(जीएनएस)।

9 मई को बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले 7 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को है। जबकि बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को है। उपलब्धि के लिहाज से भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले बिहार आ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, नवनिर्वाचित सरकार की एक सामान्य प्रक्रिया है। फिर भी नरेन्द्र मोदी और अमित शाह इस कार्यक्रम को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या इसमें कोई राजनीतिक संकेत छिपा है?

ब्रिटिश काल में पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। उस समय यह भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जब बिहार, बंगाल और ओडिशा एक प्रांत थे तब भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर उन्हें 'अंग-बंग-कलिंग' कहा जाता था। इस भौगोलिक शब्दावली की 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहुत चर्चा रही। अंग मतलब आधुनिक बिहार का भागलपुर क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के नजदीक है। बंग का मतलब पश्चिम बंगाल और कलिंग का मतलब ओडिशा।

अब इस भौगोलिक त्रिकोण में भाजपा के मुख्यमंत्री का चीर प्रशिक्षित सपना पूरा हो गया। लेकिन बिहार में यह सपना अभी भी अधूरा है। बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनका वजूद जदयू के समर्थन पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। लेकिन बिहार में वह गठबंधन की सरकार चला रही है। इसकी कसक उसे है।

7 मई को जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह पटना आएंगे तब अपने साथ पश्चिम बंगाल की रिकॉर्डतोड़ जीत की धमक भी लाएंगे। बिहार की फिजा में पश्चिम बंगाल की जीत की खुशबू होगी, जो यहां के लोगों को बहुत सिद्दत से महसूस होगी। पटना के गांधी मैदान से एक ध्वनि गूंजेगी, जिसके शब्द होंगे- 'अगर बंगाल का कठिन रण जीत लिया तो बिहार भी जीतेंगे', बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, गंगा जी पटना से बहते होते हुए पश्चिम बंगाल जाती हैं। अब जब पश्चिम बंगाल जीत लिया तो भाजपा के नेता कहेंगे- 'बंगाल की पुरवैया बयार अब बिहार आएगी।'

बंगाल की जीत ने भाजपा के आत्मविश्वास को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। यह सच है कि उसने इस सियासी जंग में वह फतह पायी है, जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। जब बंगाल जीत लिया तो बिहार क्यों नहीं जीता जा सकता? बिहार में तो वह नवम्बर 2005 (बीच में कुछ समय छोड़ कर) से सत्ता में है। इतने साल के शासन काल में तो पार्टी ने अपना एक मजबूत आधार बना लिया है।

बंगाल की तुलना में तो बिहार को अकेले जीतना ज्यादा आसान है। लेकिन बिहार की राजनीति में अलग तरह की चुनौतियां हैं। यहां नीतीश कुमार और लालू यादव के रूप में दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियां हैं, जो अभी भी बहुत प्रभावी हैं। बंगाल में तो भाजपा को सिर्फ ममता बनर्जी को मात देनी थी। वाम दल और कांग्रेस पहले ही खत्म हो गये थे। लेकिन बिहार में भाजपा को दो 'किले' (नीतीश कुमार और लालू यादव) ढहाने होंगे। यह आसान नहीं है।

आसान तो ममता बनर्जी के भी सत्ता से बेदखल करना नहीं था। लेकिन वे न केवल हारीं बल्कि बुरी तरह हारीं। 2021 में 215 सीटें जीतने वाली ममता बनर्जी 2026 में 80 पर कैसे सिमट गयीं ? दरअसल ममता बनर्जी की हार से एक बात साफ हो गयी कि अब देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आप किसी वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए अधिसंख्य लोगों के हितों की बलि नहीं चढ़ा सकते। अगर कोई नेता अल्पसंख्यकों के प्रति जरूरत से ज्यादा झुकाव दिखाएगा तो इसकी प्रतिक्रिया में बहुसंख्यक लोगों का बहुत तेज ध्रुवीकरण होगा। अगर ऐसा हुआ तो जाति से जुड़े सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के उदाहरण से समझा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में जंगल महल के नाम से जो भौगोलिक इलाका है, उसमें चार जिले आते हैं- पुरुलिया, झाड़ग्राम, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर। यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ है और यहां अधिकतर आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की बढ़ती नीति से इन चार जिलों में भी गहरी नाराजगी थी। यहां वोटरों ने जाति- वर्ग से ऊपर उठ कर ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। यह चुनाव परिणामों से साबित होता है।

भाजपा ने पुरुलिया की सभी 9 सीटें और झाड़ग्राम की सभी 4 सीटें जीत लीं। बांकुड़ा की 12 में 11 सीटें और पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 में से 13 सीटें भाजपा की झोली में गिरीं। यानी अब देश में वही राजनीति चलेगी जो सभी धर्मों और जाति को एक साथ लेकर चल सके।

जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी की राजनीति खास ढर्रे पर चल रही थी। वे समझती थीं कि 30 फीसदी (मुस्लिम) वोट तो उनका पक्का है। अगर 70 फीसदी (हिंदू) वोटों में से 20 फीसदी वोट भी बांट लिया जाए तो जीत पक्की है। लेकिन इस बार 70 फीसदी एकजुट हो गया और ममता बनर्जी हार गयीं।

अगर बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव ममता बनर्जी वाली गलती दोहराएंगे तो भाजपा के लिए यहां भी मौका बन जाएगा। इसलिए भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल से आने वाली हवा के लिए बिहार की खिड़की खोल कर रखना चाहते हैं।

सीएम योगी बोले- कीबोर्ड और डेटा अब सेना के नए हथियार, यूपी बनेगा देश की रक्षा का अभेद्य कवच

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज में आयोजित रक्षा त्रिवेणी संगम (नॉर्थ टेक सिंपोजियम-2026) के समापन समारोह में भविष्य के युद्धों और भारत की रक्षा तैयारियों का एक व्यापक खाका खींचा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक युद्ध अब केवल जल, थल और नभ की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। आज के युग में कीबोर्ड, सैटेलाइट और डेटा नेटवर्क उतने ही प्रभावी हथियार बन चुके हैं जितने कि पारंपरिक मिसाइलें और टैंक। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि

साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब नए रणक्षेत्र हैं, जहां दुश्मन के संचार और पावर ग्रिड को बाधित करना ही जीत की नई रणनीति है।

भारतीय सेना के उत्तरी तथा मध्य कमान तथा भारतीय रक्षा निमार्ता सोसायटी की ओर से न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय सिंपोजियम के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने यूपी की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जल्द ही भारत की सैन्य शक्ति का मुख्य आधार बनेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य के छह नोड्स लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर तेजी से काम हो रहा है। अलीगढ़ जहां छोटे हथियारों का केंद्र बना है, वहीं कानपुर में मिसाइल और गोला-बारूद का निर्माण हो रहा है। लखनऊ और झांसी में ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलों के निर्माण से देश की सैन्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

योगी आदित्यनाथ ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ साल पहले तक हमारा रक्षा निर्यात मात्र 600 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी 56 प्रतिशत युवा कार्यकुशल आबादी और 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ रक्षा क्षेत्र के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने नेशन फर्स्ट के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि मजबूत राष्ट्र ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। सीएम ने वहां लगी रक्षा प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, लेफ्टिनेंट जनरल वी. हरिहरन, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, एसआईडीएम के वाइस प्रेसिडेंट नीरज गुप्ता, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ए.के. घोष के साथ ही सेना के कई वरिष्ठ अधिकारीगण और स्टेकहोल्डर्स उपस्थित रहे।

सीएम ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका अब केवल पुर्जे बनाने तक सीमित नहीं है। कानपुर नोड में जहां बुलेटप्रूफ जैकेट और डिफेंस टेक्सटाइल का उत्पादन हो रहा है तो वहीं आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भविष्य की मानवरहित युद्ध प्रणाली के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। सरकार की डिफेंस एवं एयरोस्पेस पॉलिसी ने निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे पसंदीदा गंतव्य बना दिया है।

लिव-इन पार्टनर ने स्टार एक्ट्रेस को 'बाजार' में बेचा, पति ने लगाई नशे की लत, 34 साल में मिली ऐसी दर्दनाक मौत

(जीएनएस)।

हिंदी सिनेमा में कई ऐसी कहानियां हैं, जहां सफलता की ऊंचाइयों के साथ दर्द की गहरी खाई भी जुड़ी होती है। बॉलीवुड की लिजेंड्री एक्ट्रेस रह चुकीं मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा गया लेकिन एक और अभिनेत्री की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही त्रासदी से भरी रही थी।

ये कहानी है 60 और 70 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस विमी की, जिन्होंने बहुत कम समय में शोहरत हासिल की लेकिन उनका अंत बेहद दर्दनाक रहा। उनकी दर्दनाक कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया था।

-आपको बता दें कि विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखते ही दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनकी पहली फिल्म 'हमराज' सुपरहिट साबित हुई थी, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त, शशि कपूर और राज कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया था।

-इस फिल्म के बाद विमी इंडस्ट्री की नई सेंसेशन बन गई थीं। इसके बाद वह निमार्ता-निर्देशकों की पहली पसंद बनती चली गईं। 60 के दशक में विमी एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थीं जो एक फिल्म के लिए 3 लाख रुपए की फीस लेती थीं।

-विमी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थीं। वह काफी पढ़ी-लिखी थीं, कला और संगीत में गहरी रुचि रखती थीं और उनकी आवाज भी बहुत मधुर थी लेकिन परिवार को उनका फिल्मों में आना मंजूर नहीं था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने घर-परिवार से दूरी बना ली और मुंबई का रुख किया था।

-कम उम्र में विमी की शादी एक बिजनेसमैन परिवार में हुई थी और उनके दो बच्चे भी थे। बावजूद इसके, उन्होंने अपने करियर को प्राथमिकता दी थी, जिसका असर उनके निजी जीवन पर धीरे-धीरे दिखने लगा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक पार्टी के दौरान विमी की मुलाकात मशहूर संगीतकार रवि से हुई थी। उनकी खूबसूरती और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर रवि ने उन्हें फिल्मों में आने की सलाह दी थी। इसके बाद संगीतकार रवि ने ही विमी की मुलाकात फिल्ममेकर बीआर चोपड़ा से कराई थी, जिन्होंने उन्हें 'हमराज' मूवी में मौका देकर स्टार बना दिया था।

हालांकि इस फैसले की कीमत विमी को अपने परिवार से दूरी और संपत्ति से बेदखल होने, के रूप में चुकानी पड़ी थी। इसके बाद अचानक घर की जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर आ गई थीं। दरअसल फिल्मों में काम करने को लेकर विमी के ससुराल वालों ने उन्हें और उनके पति, दोनों को घर और संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी विमी पर आ गई थी।

मुंबई इंडियंस में मची खलबली, आरसीबी के खिलाफ मैच के लिए रायपुर नहीं पहुंचे कप्तान हार्दिक पांड्या

(जीएनएस)।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बीच सीजन में मुंबई इंडियंस के खेमे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने क्रिकेट जगत में चचाओं का बाजार गर्म कर दिया है। टीम के आधिकारिक कप्तान हार्दिक पांड्या बुधवार को अपनी टीम के साथ रायपुर नहीं पहुंचे हैं, जहां मुंबई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपना अगला महत्वपूर्ण मुकाबला खेलना है।

क्रिकबज के अनुसार मुंबई हवाई अड्डे पर टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ हार्दिक की अनुपस्थिति ने उन अटकलों को और हवा दे दी है जो पिछले कुछ हफ्तों से टीम के अंदरूनी कलह और नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं।

फ्रेंचाइजी की ओर से पिछली बार यह जानकारी दी गई थी कि हार्दिक पांड्या पीठ में खिंचाव यानी बैक स्पैस्म से जूझ रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेला था। लेकिन अब जब टीम रायपुर के लिए रवाना हुई और कप्तान वहां भी दिखाई नहीं दिए, तो सवाल यह उठने लगा है कि क्या यह सिर्फ एक शारीरिक चोट है या फिर कहानी कुछ और है।

खेल के जानकारों का मानना है कि अगर यह सिर्फ एक मामूली खिंचाव होता तो हार्दिक को टीम के साथ यात्रा करने और डगआउट में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। हार्दिक की गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभाल रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि उनकी कप्तानी में मुंबई ने लखनऊ के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज की।

10 मई को होने वाले मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के फैंस इस उम्मीद में हैं कि कप्तान सीधे रायपुर पहुंचेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। टीम फिलहाल अंक तालिका में नौवें स्थान पर संघर्ष कर रही है और प्लेऑफ की राह उनके लिए लगभग नामुमकिन नजर आ रही है।

ऐसे नाजुक मोड़ पर कप्तान का टीम के साथ न होना यह संकेत देता है कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाले कुछ दिन यह साफ कर देंगे कि हार्दिक पांड्या की यह दूरी केवल फिटनेस से जुड़ी है या फिर मुंबई की टीम में किसी बड़े बदलाव की कहानी लिखी जा चुकी है।

ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को पाक फौज का था सपोर्ट, नेता ने खुद कबूला, अब हुई किरकरी

(जीएनएस)।

7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा हो जाएगा। इसी बीच पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत और दुनिया के उन तमाम देशों के दावे सच साबित कर दिए जिसमें पाक द्वारा आतंकियों को पालने की बात कही जाती है। दरअसल एक पाकिस्तानी नेता के बयान ने सेना और आतंकियों के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, डिटेल में समझते हैं।

पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के अध्यक्ष शाहीर सियालवी ने रावलपिंडी में लश्कर-ए-तैयबा के एक कार्यक्रम में बड़ा खुलासा किया। शाहीर ने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इसमें वर्दी पहने सैनिकों द्वारा ताबूत उठाना और सैन्य अंतिम संस्कार शामिल था।

शाहीर ने कहा कि "हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दी के मुजाहिदीनों को इन लोगों राज्य अपना बताए। अगर चे ग्वेरा, फिदेल कास्त्रो, नेल्सन मंडेला, सुभाष चंद्र बोस और

भगत सिंह को दुनिया फ्रीडम फाइटर कहती है तो इन्हें आतंकवादी क्यों कहा जाता है। अटैक मुरीदके और बहावलपुर में हुआ था लेकिन पाक फौज ने पहली बार तय किया कि इनके जनाजे पाक फौज मौलाना पढ़ाएगा ताकि दुनिया को बता सकें ये आतंकवादी नहीं फ्रीडम फाइटर थे।"

शाहीर ये बताना भूल गया कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कभी किसी मासूम की जान नहीं ली। कभी किसी शहर में सिर्फ इसलिए दहशत नहीं फैलाई क्योंकि वहां दूसरे धर्म के लोगों ज्यादा तादाद में रहते हैं।

अब इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सियालवी के साथ मुजम्मिल हाशमी भी बैठे दिखाई देता है, जो हाफिज सईद का करीबी है और कई आतंकी वारदातों में भी शामिल रहा है।

पाकिस्तानी सरकार और आर्मी दोनों आतंकियों से दिखाने के लिए ही सही पर दूरी बनाता है। यहां तक कि कई मौकों पर उसने हाफिज सईद को दिखावे के लिए जेल में भी डाला है। लेकिन शाहीर ने पाकिस्तानी सरकार और फौज दोनों की पोल खोल दी। साथ ही सियालवी के इस बयान ने पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें वह कहता है कि उसके यहां स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट काम करते हैं।

सियालवी ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए सीजफायर का उल्लंघन किया और भारत के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने दावा किया कि सेना ने पहली बार इन लोगों के लिए सीधे तौर पर लड़ाई लड़ी।

इससे पहले भी मसूद इलियास कश्मीरी ने एक वायरल वीडियो में कहा था कि पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में अपने जनरल भेजे थे। जो बताता है कि पाकिस्तानी फौज और आतंकी अलग-अलग नहीं है।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। इसका लक्ष्य पाकिस्तान और ढड्ढङ में मौजूद आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ समय के लिए सैन्य तनाव भी बढ़ गया

क्या है पिंक प्रॉमिस मैच? आईपीएल में 9 मई को खेला जाएगा मुकाबला, राजस्थान और गुजरात में टक्कर

(जीएनएस)।

राजस्थान रॉयल्स ने घोषणा की है कि 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाला घरेलू मैच फ्रेंचाइजी का 'पिंक प्रॉमिस' मैच होगा। यह एक विशेष मुकाबला है जो अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। रॉयल राजस्थान फाउंडेशन (RRF) द्वारा संचालित यह पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवर्तन की दिशा में राजस्थान रॉयल्स की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

राजस्थान रॉयल्स की सामुदायिक पहलों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका यह मैच टीम को उनकी खास ऑल-पिंक जर्सी में मैदान पर उतरते हुए देखेगा, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले बदलाव के प्रति उनकी निरंतर निष्ठा का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में यह पहल क्रिकेट की पहुंच का उपयोग कर मैदान के बाहर भी वास्तविक और प्रभावशाली बदलाव लाने का एक मजबूत मंच बन चुकी है। पिंक प्रॉमिस फ्रेंचाइजी की वह मुहीम है, जो "औरत है तो भारत है" की सोच के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करती है।

इस सीजन की पिंक प्रॉमिस जर्सी अपने साथ एक गहरी कहानी लेकर आई है। इसे 'Royals HunaRR Manch - Season 2 राजस्थान रॉयल्स पिंक प्रॉमिस जर्सी डिजाइन प्रतियोगिता' के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें देशभर के 700 से अधिक डिजाइनर्स ने 8,500 से अधिक प्रविष्टियां भेजी थीं। यह जर्सी जमीनी स्तर पर बदलाव की भावना को दशार्ती है। महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवर्तन की सोच पर आधारित इस डिजाइन में एक सूक्ष्म 'रिपल पैटर्न' शामिल है, जो यह दशार्ता है कि कैसे एक व्यक्ति से शुरू हुआ बदलाव परिवारों और समुदायों तक फैलता है। इस विजेता डिजाइन को नासिक की 19 वर्षीय समीक्षा रामेश्वर मुंडाडा ने तैयार किया है।

इस जर्सी में सोलर-प्रेरित डिजाइन एलिमेंट्स भी शामिल हैं, जो स्वच्छ और सतत ऊर्जा तक पहुंच का प्रतीक हैं। साथ ही, इसमें रॉयल राजस्थान फाउंडेशन द्वारा समर्थित महिलाओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। ये सभी तत्व मिलकर "औरत है तो भारत है" की भावना को जीवंत करते हैं और इस जर्सी को केवल एक खेल किट नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव की एक मिसाल बनाते हैं।

इस पहल पर बात करते हुए राजस्थान रॉयल्स के मुख्य परिचालन अधिकारी आलोक चित्रे ने कहा कि पिंक प्रॉमिस पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत अभियान बन चुका है, जहां क्रिकेट मैदान के बाहर भी सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रहा है।

उन्होंने बताया कि 2024 में इस पहल ने 260 घरों को रोशन करने में मदद की, जिसके बाद 2025 में यह संख्या 520 से अधिक घरों तक पहुंच गई। एक और सीजन में प्रवेश करते हुए टीम इस प्रभाव को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस वर्ष भी राजस्थान रॉयल्स क्षेत्र में सोलर विद्युतीकरण के अपने प्रयास जारी रखेगा। मैच के दौरान लगाए गए हर छक्के पर 6 घरों को सोलर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा, जिससे खेल के प्रदर्शन और सामाजिक सरोकार के बीच का संबंध और मजबूत होगा।

चित्रकूट डिफेंस कॉरिडोर शिलान्यास 11 को, सीएम योगी और राजनाथ सिंह के आगमन पर बहुस्तरीय सुरक्षा

(जीएनएस)।

चित्रकूट। पहाड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित डिफेंस कारिडोर परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। 11 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को डिफेंस कारिडोर परियोजना स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पिकेटिंग, बैरिकेडिंग, यातायात प्रबंधन, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसी आपात सेवाओं की व्यवस्था को बारीकी से परखा। एसपी ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और सुरक्षा प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया जाए। भीड़ नियंत्रण, वीआईपी मूवमेंट और आमजन की सुविधा को ध्यान में

रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि कार्यक्रम के दौरान निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कार्यक्रम को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। उनका कहना है कि डिफेंस कारिडोर का यह शिलान्यास कार्यक्रम जिले के लिए ऐतिहासिक होगा और इसे पूरी सुरक्षा व सुव्यवस्था के साथ संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

बता दें कि चित्रकूट में पहली डिफेंस फैक्ट्री को भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) विकसित कर रही है। करीब 562.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह इकाई 75 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी, जहां अत्याधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना न केवल देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती देगी, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक मानचित्र पर भी स्थापित करेगी।

कहां-कितने बजे विजय लेंगे सीएम पद की शपथ? राहुल गांधी समेत किसे आमंत्रण?

(जीएनएस)।

तमिलनाडु की राजनीति में एक और ऐतिहासिक पल आने वाला है। थलापति जोसेफ विजय चंद्रशेखर की तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुमत (118) से 10 सीटें कम रहने के बावजूद कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया।

अब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हो चुका है कि 7 मई 2026, सुबह 11:30 बजे, चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में थलापति विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह समारोह सिर्फ शपथ नहीं, बल्कि तमिलनाडु की 60 साल पुरानी द्रविड़ राजनीति के अंत और कोएलिशन पॉलिटिक्स की शुरूआत का प्रतीक है।

सबसे चर्चित नाम है 'राहुल गांधी'। टीवीके चीफ विजय ने खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर शपथ समारोह में आमंत्रित किया है। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने पुष्टि की कि विजय ने राहुल गांधी और

खड़गे जी को फोन किया, धन्यवाद दिया और शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही राहुल जी की उपस्थिति की आधिकारिक पुष्टि कर दी जाएगी।

राहुल गांधी पहले ही विजय को फोन कर जीत पर बधाई दे चुके हैं और युवाओं की आवाज को नजरअंदाज न करने की बात कही थी। अगर राहुल समारोह में पहुंचे तो यह टीवीके-कांग्रेस गठबंधन की मजबूती का सबसे बड़ा संदेश होगा।

डीएमके खेमे में तनाव चरम पर है। पिछले 20 साल से चला आ रहा DMK-कांग्रेस गठबंधन औपचारिक रूप से खत्म हो गया। कांग्रेस ने सत्ता में हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन DMK ने मना कर दिया। नतीजा ये है कि

कांग्रेस ने टीवीके का हाथ थाम लिया।

डीएमके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने "धोखा" दिया। स्टालिन खेमे में नाराजगी इतनी है कि अब लोकसभा में भी कांग्रेस के मुद्दों का समर्थन न करने की बात हो रही है। क्या DMK INDIA गठबंधन में बनी रहेगी? यह सवाल अब गंभीर हो गया है।

विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात - राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु आए थे। सूत्रों का दावा है कि उन्हें कांग्रेस के इस कदम की पहले से जानकारी थी और वे एमके स्टालिन से मिले बिना ही चले गए। यह ऊटङ के लिए और भी कड़वा है।

राजनीतिक महत्वः पहला गैर-द्रविड़ CM, कोएलिशन का नया युग

यह शपथ समारोह तमिलनाडु के लिए में मील का पत्थर है:

पहला गैर-DMK/AIADMK CM: 1967 के बाद पहली बार कोई गैर-द्रविड़ पार्टी की सरकार।

लखनऊः चारबाग और लखनऊ जंक्शन पर फिर शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा, यात्रियों को मिलेगी मनमाने किराए से राहत

(जीएनएस)।

लखनऊः आने वाले दिनों में चारबाग रेलवे स्टेशन या लखनऊ जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों को शहर के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए साधनों के अभाव में भटकना नहीं पड़ेगा. इतना ही नहीं, यात्रियों को सार्वजनिक साधनों के लिए मनमाना किराया भी नहीं चुकाना होगा क्योंकि पिछले पांच साल से बंद पड़ी प्रीपेड ऑटो सेवा को एक बार फिर बहाल करने की तैयारी की जा रही है.

यह सेवा रेलवे द्वारा इसलिए शुरू की जा रही है ताकि यात्रियों को लोकल स्थानों पर जाने के लिए ठगी का शिकार न होना पड़े. परिवहन विभाग की ओर से तय किराए पर ऑटो बुक करके यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे.

यात्रियों की सुविधा के लिए फिर शुरू होगी सेवाः उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए इस सेवा को पुनः शुरू करने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से यह सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी.

पांच साल पहले 2019 में जब यह सेवा शुरू हुई थी, तो जीआरपी बूथ पर ही ऑटो की बुकिंग होती थी और ड्राइवर का नाम व ऑटो नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाता था. यात्री किराया बूथ पर जमा करते थे और यात्रा पूरी होने पर ड्राइवर को दी गई पर्ची का वेरिफिकेशन किया जाता था.

बंद पड़े प्रीपेड बूथ फिर सक्रिय किये जाएंगेः इस व्यवस्था का लाभ यह था कि यात्रियों को 24 घंटे ऑटो की सुविधा मिलती थी और देर रात या तड़के ज्यादा किराया वसूलने की समस्या से निजात मिलती थी. महिला यात्री भी प्रीपेड ऑटो में खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करती थीं, क्योंकि जीआरपी के पास चालक का पूरा रिकॉर्ड रहता था. हालांकि, यह सेवा कुछ समय बाद किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी और आज वही प्रीपेड बूथ सालों से ताले में बंद पड़ा है. अब यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने फिर से इस बूथ और सेवा को सक्रिय करने का मंथन शुरू कर दिया है.

फिर से शुरू होगी पारदर्शी प्रीपेड ऑटो बुकिंगः चारबाग स्टेशन के बाहर अभी भी प्रीपेड ऑटो सेवा का पुराना बोर्ड और किराए की सूची चस्पा है, लेकिन वहां से बुकिंग बंद है. अब रेलवे का प्रयास है कि इसी पुराने बूथ के माध्यम से फिर से बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि यात्रियों को पारदर्शी किराया मिल सके. सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने दोहराया कि जल्द ही प्रीपेड ऑटो सेवा को धरातल पर लाने का प्रयास किया जाएगा. यह पहल न केवल यात्रियों के समय और धन की बचत करेगी, बल्कि लखनऊ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए यात्रा को अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाएगी.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रात 2 से 4 बजे तक सफर खतरनाक, 73 किमी में 2 माह में 13 की गई जान

(जीएनएस)।

तिर्वा (कन्नौज)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर करना है तो रात दो बजे से तड़के चार बजे के बीच बिल्कुल न करें। यह समय नींद का होता है। सफर करते समय रात में रेस्ट एरिया देखें और नींद पूरी करें। इसके बाद आगे का सफर सुरक्षित तय करें। नान स्टाप आगरा से लखनऊ का 302 किमी का सफर तय करना खतरे से खाली नहीं रहता।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ठठिया से सौरिख के बीच करीब 73 किलोमीटर का सफर रहता है। इस बीच दो माह के अंतराल में करीब 13

से अधिक की मौत हो चुकी हैं। यह सभी हादसे वाहन चालक को झपकी आने के कारण हुए हैं। इसके अलावा इन सभी हादसों का समय भी रात करीब दो बजे से सुबह चार बजे के बीच रहा है। कारण, इस बीच चालक को नींद आना तय होता है।

एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटे से कम नहीं रहती। तेज रफ्तार में जरा सी चूक पर वाहन चालक हादसे के शिकार हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी सलाह देते हैं कि एक्सप्रेसवे पर आधी रात के बाद रेस्ट एरिया में वाहन को खड़ा कर लें और नींद पूरी होने के बाद ही सफर तय करें।

सुरक्षित सफर तभी रहेगा, तब सावधानी खुद बरतेंगे। रात दो बजे से सुबह चार बजे का समय नींद आने का होता है। इस बीच वाहन चालक को नींद आनी तय होती है। ऐसे में रेस्ट एरिया में वाहन खड़ा करें और नींद पूरी करने के बाद सुरक्षित सफर तय करें।'

कुलवीर सिंह, सीओ, तिर्वा

छावनी परिषद प्रशासन लखनऊ की संवेदनहीनता, बेटी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को खिलाया प्रसाद तो पिता को किया पदावनत

(जीएनएस)।

लखनऊ। छावनी परिषद प्रशासन में एक सुपरवाइजर को काम से हटाकर सफाईकर्मी के पद पर स्थानांतरित करने को लेकर विवाद हो रहा है। सफाई सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहे उमेश कुमार को सफाई कर्मी बना दिया गया है।

परिषद प्रशासन का कहना है कि कर्मचारी उमेश कुमार ने बिना अनुमति के रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भंडारे के लिए आमंत्रित किया था। उमेश कुमार का आरोप है कि उनकी बेटी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भंडारे का प्रसाद खिलाया था, जिसके कारण परिषद प्रशासन ने उनके मूल पद पर वापस भेजकर सफाई कर्मी बना दिया है।

उल्लेखनीय है कि अंजली मैसी ने 14 अप्रैल को छावनी परिषद के गेट

के पास बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर भंडारे का आयोजन किया था। इसी दिन बैसाखी पर्व पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सदर गुरुद्वारा में माथा टेकने गए थे। गुरुद्वारा से निकलते समय अंजली मैसी ने अखिलेश यादव से भंडारे का प्रसाद खाने का आग्रह किया था। गाड़ी से उतकर अखिलेश ने प्रसाद के रूप में सब्जी पूड़ी खायी थी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ।

इसके बाद 16 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए छावनी परिषद प्रशासन ने अंजली मैसी के पिता उमेश कुमार को तत्काल प्रभाव से सफाई का काम करने के आदेश जारी कर दिए। इससे पहले 16 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन सफाई अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए उमेश कुमार को स्थाई रूप से अगले आदेशों तक विभिन्न प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में लगे चौकीदार और गार्ड की ड्यूटी संबंधी जानकारी सफाई विभाग को देने का दायित्व सौंपा था। यह कार्य सुपरवाइजर का होता है।

आप बंगाल में उलझे रहे, इधर मालदीव और श्रीलंका ने कर ली बड़ी डिफेंस डील, निशाने पर आएगा भारत का पड़ोसी देश?

(जीएनएस)।

मालदीव और श्रीलंका ने हाल ही में सात समझौतों पर साइन किए। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा डिफेंस पर साइन हुए टङ्कव की हो रही है। यह समझौते कोलंबो में हुए, जहां मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मुइज्जू 4 मई 2026 को राजकीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे थे, जब भारतीय लोग बंगाल समेत पांच राज्यों को चुनाव नतीजों में व्यस्त थे।

वार्ता के बाद मुइज्जू ने कहा कि यह दौरा सिर्फ पड़ोसी रिश्तों की पुष्टि नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच एक नई और भविष्य को ध्यान में रखने वाली साझेदारी की शुरूआत है। उन्होंने बातचीत को काफी हद तक प्रोडक्टिव बनाए रखने पर फोकस किया।

मुइज्जू ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, युवा और खेल, मत्स्य पालन, पर्यावरण और सामाजिक विकास जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। एक्सपर्ट की मानें तो बाकी 6 समझौते दोनों देशों के बीच पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन रक्षा पर

समझौता हिन्द महासागर की शांति में एक अलर्ट की तरह है। क्योंकि इस वक्त मालदीव और मॉरीशस के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका का उसके साथ डिफेंस डील करना गौर करने वाली बात है।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चागोस द्वीप समूह पर ऐतिहासिक और कानूनी दावा जताया है। उनका कहना है कि इन द्वीपों पर 900 साल पुराने मालदीव से जुड़े अवशेष मिले हैं, जो इस दावे को मजबूत करते हैं।

2023 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (ITLOS) ने चागोस क्षेत्र के समुद्री हिस्से का बड़ा भाग मॉरीशस को देने का फैसला सुनाया था। हालांकि, मालदीव की पिछली सरकार ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है।

इस विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। मालदीव ने विवादित क्षेत्र में अपनी नेवी तैनात कर दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और गहरा कर रहा है। जिसमें अगर श्रीलंका शामिल होता है तो तनाव और बढ़ सकता है।

भारत के लिए क्या चुनौती?

इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर भी पड़ा है। एक क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते भारत को मालदीव और मॉरीशस दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होते हैं। ऐसे में यह विवाद भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाना और मुश्किल कर रहा है।

इन सात टङ्कव में पर्यटन, अभिलेखागार, टीचर ट्रेनिंग, खेल और युवा विकास, रक्षा, रक्षा शिक्षा और रिसर्च, और कोलंबो विश्वविद्यालय के साथ-साथे मालदीव के संस्थानों के बीच एकेडमिक सपोर्ट शामिल है। देखना होगा आने वाले वक्त में श्रीलंका का डिफेंस के मामले में क्या रुख रहता है और अगर टेंशन बढ़ती है तो क्या भारत कैसे इसमें शांति लाएगा।

ईरान के पीछे चट्टान बनकर खड़ा हुआ चीन, दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच डील, टेंशन में ट्रंप

(जीएनएस)।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश शुरू हुई है। खबर है कि दोनों पक्ष 14-पॉइंट के समझौते (टङ्कव) पर विचार कर रहे हैं, ताकि युद्ध का खतरा टल सके। इसी बीच, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री की बीजिंग में हुई मुलाकात ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है।

एक तरफ अमेरिका से समझौते की सुगबुगाहट है, तो दूसरी तरफ चीन का मजबूत समर्थन। ईरान इस समय 'धमकी और समर्थन' के बीच अपनी सुरक्षा और कूटनीति का नया संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

ईरान और अमेरिका के बीच चल रही दुश्मनी को थामने के लिए एक संभावित समझौते की बात सामने आ रही है। इस 14-पॉइंट के फॉमूर्ले का मुख्य उद्देश्य फिलहाल युद्ध जैसी स्थिति को रोकना है। इसमें परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय संघर्षों पर बातचीत के रास्ते खोलने की तैयारी है। यह समझौता ईरान के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, क्योंकि इससे उस

पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में ढील मिल सकती है और क्षेत्र में शांति की उम्मीद जग सकती है।

अमेरिका से बातचीत के बीच, चीन ने ईरान को खुलकर समर्थन देकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि वे ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा में उसके साथ हैं। यह मुलाकात दिखाती है कि ईरान केवल अमेरिका के भरोसे नहीं है, बल्कि उसके पास चीन जैसा शक्तिशाली विकल्प भी मौजूद है। चीन का यह 'सपोर्ट एंगल' ईरान को बातचीत की मेज पर मजबूती से बैठने की ताकत देता है, ताकि वह दबाव में न आए।

इस समय पूरा इलाका बारूद के ढेर पर खड़ा है, जहां जरा सी चूक युद्ध भड़का सकती है। चीन ने साफ किया है कि अब और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चीन खुद को एक 'मध्यस्थ' के रूप में देख रहा है, जो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बीजिंग की कोशिश है कि युद्ध रुके और बातचीत के जरिए शांति बहाल हो, जिससे न केवल ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में स्थिरता आ सके। ईरान इस समय बड़ी चतुराई से अपनी चालें चल रहा है। एक तरफ वह अमेरिका के साथ समझौते की संभावनाओं को तलाश रहा है, ताकि सीधे टकराव से बचा जा सके। दूसरी तरफ, चीन के साथ अपने रिश्तों को और गहरा कर रहा है ताकि अमेरिका उसे अलग-थलग न कर पाए। यह 'डबल गेम' ईरान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुरक्षा देता है। चीन का साथ और अमेरिका से समझौते की बातचीत, दोनों मिलकर इस क्षेत्र की राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली प्रचंड जीत, भाजपा ने जीती कितनी एससी, एसटी सीटें? हैरान कर देंगे आंकड़ें

(जीएनएस)।

4 मई 2026 को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों ने देश की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने असम और पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत हासिल कर सभी को हैरान कर दिया। वहीं दोनों ही राज्यों में रउ/रळ आरक्षित सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए यह साबित कर दिया है कि पार्टी अब सामाजिक रूप से भी अपनी जड़ें गहरी कर चुकी है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सेड्यूल कास्ट(SC) की 68 में से 51 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) केवल 17 सीटों तक सिमट गई। यह दलित वोट बैंक के clear consolidationका संकेत देता है।

वहीं Scheduled Tribe (ST) सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन और भी ज्यादा dominant रहा-पार्टी ने सभी 16 सीटों पर जीत दर्ज की। उत्तरी बंगाल और जंगलमहल जैसे आदिवासी क्षेत्रों में यह एकतरफा जनादेश भाजपा के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है ।कुल मिलाकर भाजपा ने 84 SC/ST सीटों में

से 67 सीटें जीतकर विपक्ष को लगभग साफ कर दिया।

असम में भी तस्वीर काफी हद तक समान रही। 9 रउ सीटों में भाजपा ने 5 जीतीं, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 8 सीटों पर कब्जा किया।

ST सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा-19 में से 13 सीटें भाजपा के खाते में गईं और NDA ने सभी 19 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें सहयोगी दल बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) और असम गण परिषद (AGP) की अहम भूमिका रही।

विश्लेषकों का मानना है कि परिसीमन (delimitation) ने भी इन नतीजों में अहम भूमिका निभाई। रळ सीटों की संख्या 16 से बढ़कर 19 और SC सीटें 8 से बढ़कर 9 होने से चुनावी गणित बदल गया, जिसका फायदा ठऊअ को मिला।

असम में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत पार किया। ठऊअ ने 126 में 100+ सीटें जीतकर तीसरी लगातार सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ किया ये परिणाम साफ दिखाते हैं कि SC/ST वोट बैंक अब decisive factor बन चुका है।

तमिलनाडु में NDA के सहयोगी AIADMK ने 46 SC सीटों में से 9 और 2 ST सीटों में से 1 पर जीत दर्ज की।

पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 5 SC सीटों में से 2 जीतकर गठबंधन की उपस्थिति मजबूत की।

इन चुनाव परिणामों ने यह संकेत दिया है कि भारत की राजनीति में एक बड़ा सामाजिक और चुनावी पुनर्गठन हो रहा है, जहां SC/ST समुदाय अब निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं-और फिलहाल यह झुकाव भाजपा और NDA के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है।